



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६]

No. ६]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी ३, १९७९/पौष १३, १९००

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 1979/PAUSA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न वी जाती हैं जिससे इक पह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

आधिकार, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता भंडालय

(आधिकार विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० ४ ईटीसी (पीएम)/७९

नई दिल्ली, ३ जनवरी, १९७९

(निर्वाचित व्यापार नियंत्रण)

विषय : १-१-१९७९ से ३१-१२-७९ तक बुना सामान्य लाइसेंस-३
के आधीन तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्तों सहित
(ताग, घे गुडस, टेरी टाथल व टावलिंग को छोड़कर) मिल
से बने हुए/विजली बरखे/हथकरघे से तैयारी सूती वस्तु और तिविधि
वस्तु उत्पाद को आस्तिया को नियंत्रित करने की योजना।

बिं. सं० २/१/७९-१। —उपर्युक्त विषय पर नियंत्रित (नियंत्रण)
संबोधन आदेश सं० ई (सी) ओ. १९७७/ एम (८७) दिनांक
३ जनवरी, १९७९ की ओर व्यापार विभाग जाता है।

२. यह योजना कोटा खर्च १ जनवरी, १९७९ से ३१ दिसंबर, १९७९
तक तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्तों सहित (ताग, घे
गुडस, टेरी टाथल और टावलिंग को छोड़कर) मिल से बने/विजली बरखे/
हथकरघे से बने हुए तैयार वस्तुओं और कपास के विविध उत्पादों के
आस्तिया को नियंत्रित करने से संबंधित है।

३. कोटा आबंटन के उद्देश्य के लिए पोतलदास भविष्य छ-ळळ: महीनों
की दो अवधियों अर्थात् १ जनवरी, १९७९ से ३० जून १९७९ और १
जुलाई, १९७९ से ३१ दिसंबर, १९७९, में विभाजित की जाएगी। वार्षिक
कोटे का ६०% प्रथम ६ महीनों के दौरान आबंटित किया जाएगा और
बाके ४०% भग्ने ६ महीनों के दौरान।

१० ३८८/७८

(31)

४. कोटा खर्च की प्रथम छमाही की मात्रा पर निर्भर करते हुए इस
विभाजन पर मरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। सूती वस्तु नियंत्रि
त संबंधित परिषद बम्बई वस्तों और बनी हुई वस्तुओं के लिए और परिषाम
नियंत्रित संबंधित परिषद, नई दिल्ली पोशाकों और सलाई से बने हुए वस्तों
के लिए कोटा आबंटित करेगी।

५. वस्तों और बनी हुई वस्तुओं के कोटे का ५०% का नियंत्रण
तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा
और शेष ५०% का नियंत्रण पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले
पाए के आधार पर किया जाएगा। प्रावधानकालीन, पर निर्भर करते हुए
तैयार माल आबंटन और पक्की संविदा आबंटन के संबंधित अनुपात का संमज्ज्वल
जब कभी सरकार आवधक समझे कर सकती है।

६. पोशाकों और सलाई से बने हुए वस्तों के लिए कोटे के ४०% का नियंत्रण
तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर और शेष
६० प्रतिशत पक्की संविदाओं के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार
पर किया जाएगा। इन दोनों पद्धतियों में से प्रत्येक के अन्तर्भृत कोटे
के २० प्रतिशत का नियंत्रण उच्चतर मूल्य की मर्दों के लिए किया जाएगा।
यदि उच्चतर कीमत नियंत्रण का भाग पहले समाप्त हो जाता है तो।
उच्चतर कीमत वाला माल स्वाभाविक रूप से भय माल के साथ अन्य
भाग में प्रवाहित करेगा। इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम मूल्य के दो
प्राधार होंगे—एक का संबंध २० प्रतिशत आबंटन द्वारा उच्च मूल्य मर्दों
के साथ और दूसरा ८० प्रतिशत आबंटन के द्वारा आगे वाले मर्दों के लिए
स्थूलतम मूल्य का आधार होगा। सूती पोशाकों और सलाई से बुने हुए
वस्तों के लिए कोटा आबंटन साखपत्र शर्तों पर किया जाएगा। तैयार माल
के आबंटन के लिए पहले पाए सो पहले प्राप्त के आधार पर साखपत्र

कोटा पृष्ठांकन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पक्के आवेदा प्रावेटन के लिए पहले आए सी पहले पाए के आधार पर सामग्री कोटा आबंटन के 60 दिनों के भीतर अधिकारी पातलदान के लिए कोटा पृष्ठांकन से पहले भी भी इनमें पहले आता हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर कोटा प्रावेटन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

7. पहले आए सी पहले पाए तैयार माल पर कोटा प्रावेटन के मद्देन पोतलदान कोटा पृष्ठांकन की तिथि में 10 दिनों के भीतर करना होगा। लेकिन कई मामलों में उचित कार्यालयों के लिए वस्त्र आयुक्त अधिकारी उसके प्रतिनिधि के विशिष्ट ग्रन्तीकरण पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

8. पहले आए सी पहले पाए पक्की संविदा निवारण के मामलों में यदि प्रस्ताव अतिम तिथि तक उपलब्ध कोटा से अधिक है तो इस उद्देश्य के लिए इन वस्त्रालयों में से एक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, चुनाव एकक मूल्य के आधार पर किया जाएगा। ऐसे ग्रन्तीकरण पर उचित एकक मूल्य मापदंड होगा। उन मामलों में, अन्तिम तिथि को बच्चों की पौशाकों के लिए विशेष प्रावेटन पर विचार किया जाएगा और मुख्या प्रदान की जाएगी।

9. नियात संबंधित परिषद या उसकी प्राविधिक अंतर्वर्ती प्रतिनिधियों द्वारा पृष्ठांकन के समय आरी किए गए नियात प्रमाणपत्र के आधार पर आयातक की जारी किए गए आयात साइरेस के मद्देन आस्ट्रिया में आयात की अनुमति दी जाएगी। नियात प्रमाणपत्र क्रेन के लिए है और इस लिए पांचवर्षिक अवधि नियात संबंधित परिषद् में उसे प्राप्त करने पर अन्य सम्बद्ध दस्तावेजों सहित अपने क्रेन को भेजना चाहिए।

10. जब कभी प्रेयित माल पोतलदान के लिए तैयार हो तो नियातिक प्रावेष्यक पोतलदान दस्तावेज (जिसमें पोतलदान विलों की दो प्रतियां शामिल हैं) यदि कोई हो तो, कोटा प्रमाणपत्र महित, नियात संबंधित परिषद अधिकारी इसके अन्तर्वर्ती पत्तन प्रतिनिधियों को कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेगा। पोतलदान विलों की दो प्रतियां शामिल होने के प्रत्येक माल के ब्लॉरों की पूरा करते हुए एक प्रावेटन प्रपत्र, कोटा लाइसेंस पृष्ठांकन जारी करते समय प्रावेष्यक नियात प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भेजेंगे। इसके पश्चात् दस्तावेज पोत, परिषद दस्तावेज, पोत परिषद विलों सहित, और अन्य कार्रवाई पूरी करते के लिए सीमाशुल्क को भेजे जाएंगे। तैयार पौशाकों के मामलों में पोतलदान दस्तावेज जिसमें पोत परिषद विल भी शामिल है परिषद नियात संबंधित परिषद अधिकारी इसके अन्तर्वर्ती पत्तन प्रतिनिधियों को पोतलदान पत्तन पर सीमाशुल्क विभाग द्वारा पोतलदान विल अंकित करने से पहले कोटा पृष्ठांकन के लिए भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इन सभी मामलों में पोतलदान विलों को इस सम्बद्ध नियात संबंधित परिषद अधिकारी इसके अन्तर्वर्ती पत्तन प्रतिनिधियों को सीमाशुल्क विभाग से पोत परिषद विलों की संख्या और विनाक एकद करने के बाद सूचित करता होगा।

11. जहाँ तक कुटीर उद्योग के हथकरघा वस्त्र, ऐसे ही हथकरघा वस्त्रों से नियात हस्तगिरित कुटीर उद्योग उत्पादों ऐसे, ही हथकरघा वस्त्रों से नियात जीवी हुई पौशाकों और परम्परागत लौकिक हस्तशिल्प वस्त्र उत्पादों का संबंध है आस्ट्रिया को नियात के लिए इनका पोतलदान, वस्त्र आयुक्त या प्रबिल भारतीय हस्तशिल्प जोई जैसा भी मामला हो, के द्वारा जारी किए गए उपयुक्त प्रमाणपत्र के आधार पर सीमाशुल्क द्वारा अनुमित किया जाएगा। इन मद्दों के लिए, सीमाशुल्क प्राविधिकारियों द्वारा पोत परिषद विलों के पृष्ठांकन के लिए किसी भी सम्बन्धित नियात मंबद्ध परिषद के कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

12. कोटा प्रावेटन से सम्बन्धित मामलों में वस्त्र आयुक्त, बम्बई अधिकारी उसके द्वारा मनोनीत एक अधिकारी को दिन-प्रतिदिन देखरेख करनी होगी। वस्त्र आयुक्त अधिकारी के रूप में और मनोनीत विभिन्न नियाति संबंधित परिषदों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय समिति समय-समय पर स्थिति की पुनरीक्षा करेगी।

13. पक्के वायदों पर पहले आए सी पहले पाए के आधार पर कोटा प्रावेटन के लिए आवेदक का आवेदक पत्र के साथ पौशाकों और चुन-दून-ए वस्त्रों के लिए काटा प्रावेटन का जटाज पर निशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत भाग के लिए नियादान बाष्प प्रस्तुत करना होगा। पहले आए सी पहले पाए के आधार पर तैयार माल के कोटा प्रावेटन के मामले में एक रूपया प्रति नग की दर से अधिकारी जटाज पर निशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत अधिक धन जो भी इनमें अधिक हो कोटा पृष्ठांकन के समय आवेदक की जमा करना पड़ेगा। कोटा प्रावेटन/कोटा पृष्ठांकन की वैध की अवधि के बीचारा यदि उपयोग 90 प्रतिशत से कम नहीं है तो नियाति का साथ्य प्रस्तुत करने पर जमा किए हुए अधिक धन/निष्पादन बाष्प का पूर्ण धन वापस कर दिया जाएगा। यदि कोटा प्रावेटन का उपयोग 90 प्रतिशत से कम है तो नियादान बाष्प के पूर्ण धन पर जुमानी दिया जाएगा और जमा किया हुआ पूर्ण अधिक धन जमा किया गया समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि अधिकारी कोटा प्रावेटन के 25 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे भागी के लिए आगे कोटा प्रावेटन की अन्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। लेकिन प्रधान भागी की भागी में उचित छूट पर विचार किया जा सकता है।

14. नियात भारत में किसी भी पत्तन में अनुमित किया जाएगा।

15. नियात संबंधित परिषदों के पते इन प्रकार हैं:—

(1) सूती वस्त्र नियाति संबंधित परिषद
“इंडीनियरिंग सेट्टर”
9, मैथ्यू रीड पांचवीं मंजिल,
बम्बई-400004

(2) परिषदान नियाति संबंधित परिषद,
सहयोग चिल्डिंग, चौथी मंजिल,
58 नेहरू प्लैस, नई दिल्ली-110019

16. वे अकिं जिन्हें उपर्युक्त व्यवस्याओं के प्रत्युपार कोटा दिया गया है, परन्तु जिन्होंने कोई पूरा उत्पाद नहीं किया है उन्हें आगामी कोटा प्राप्त करने से बंचित कर दिया जाएगा इसके साथ-साथ इस भारे में उन पर अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

17. नियात नीति 1978-79 के अध्याय-2, पृष्ठ-29 पर क्रम संख्या 70(7) के सामने विद्यमान प्रविष्टि इस प्रकार प्रतिस्थापित की जाएगी:—

“70(7) मिल नियाति/विजिली करवा नियाति खुले मामलान्व साइरेस 3 के सूती हथकरघा परिषद ग्रन्तीत नियाति विजिलिंग के अधीन वस्त्र और विविध वस्त्र अनुमित किया जाएगा:—
उत्पादों (याने देगुड्स, टैरी 1. कोटा प्रावेटन के महे नियाति लियिंग को छारा:—
कर) जिसमें सीयार पौशाकों (क) वस्त्रों और बनी हुई वस्तुओं
और सलाई से बने हुए पह- के लिए सूती वस्त्र नियाति
नावों का आस्ट्रिया की संबंधित परिषद
नियाति।

1

2

3

(स) पोशाकों और सवाई में
मनी हुई पोशाकों के लिए
परिधान निर्यात संबंधित परिवहन
पोत परिवहन विलों पर
पूँछांकन के द्वारा।

2. हथकरघा वस्त्रों का निर्यात, वस्त्र
आयुक्त या अखिल भारतीय हस्त-
शिल्प बोर्ड जैसा भी मामला हो,
में हथकरघा मूलता का वस्त्रि
हुए प्रभाग-पद के आधार पर किसी
भी कोटा प्रतिबन्धन के बिना ही अनु-
मित किया जाएगा।

का० व० सेपाहि, मुख्य नियंत्रक, भारत-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO 4- ETC (PN)/79

New Delhi, the 3rd January, 1979

Sub : Scheme for exports under OGL. 3 of mill-made/
powerloom/handloom finished fabrics and misc.
textile products of cotton (other than yarn, grey
goods, terry towels and towelling) including ready-
made garments and knitwear to Austria from 1-1-1979
to 31-12-1979.

F. No. 2/1/79.E.I.—Attention is invited to the Exports
(Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM (87), dated
3rd, January, 1979, on the above subject.

2. The scheme relates to the exports of finished fabrics and
miscellaneous products of cotton (other than yarn, grey goods,
terry towels and towelling) of mill-made/powerloom/handloom
fabrics including Ready-made garments and knitwear to Austria
for the quota year 1st January, 1979 to 31st December, 1979.

3. For the purposes of quota allotment, the shipment period
will be divided into two six-monthly periods i.e., from 1st January
1979 to 30th June, 1979 and from 1st July, 1979 to 31st December,
1979. 60% of the annual quota will be allocated during the
first six months and the rest 40% during the next six months.

4. Depending upon the demand in the first half of the quota
year, readjustments of this division may be considered by the
Government. The Cotton Textiles Exports Promotion Council,
Bombay will allocate quotas for fabrics and made-ups and the
Apparel Export Promotion Council, New Delhi will allocate
quota for garments and knitwear.

5. For fabrics and made-up articles, 50% of the quota will
be allocated on first-come first-served basis for ready goods and
the rest 50% on first-come first-served basis for firm contracts.
Depending upon the need, adjustment of the related proportion
of ready goods allocation and firm contracts allocation may be
made by the Government whenever it is found necessary.

6. For garments and knitwear, 40% of the quota will be
allocated on first-come first-served basis for ready goods and
the rest 60% on first-come first-served basis for firm contracts.
Under each of these two systems, 20% of the quota will be allo-
cated for higher value items. In case the portion for higher
price allocation gets exhausted first, the goods with higher price

will naturally have the eligibility in the other portion alongwith
the other goods. For this purpose, there will be two sets of
floor prices—one relating to higher value items covered by 20%
allocation and the other base floor price for items covered by the
remaining 80% of the allocation. Quota allocation for gar-
ments and knitwear will be made on LC terms. For first-
come, first-served ready goods allocation, LC should be pro-
duced at the time of quota endorsement and for first-come
first-served firm contract allocation, LC should be produced
within 60 days of quota allocation or before quota endorsement
for shipment, whichever is earlier, failing which quota allocation
will be automatically deemed to lapse.

7. Shipments against quota allocations on first-come, first-
served ready goods basis will have to be effected within 10 days
from the date of quota endorsement. However, this period can
be extended in exceptional cases for valid reasons on specific
authorisation from the Textile Commissioner or his representa-
tive.

8. In the case of first-come, first-served firm contract
allocation, if the offers are more than the quota available
on the terminal date, a choice among offers may have to be
made and, for this purpose, selection will be made on the basis
of unit price. The higher unit price will be the criterion in such
an eventuality. In that case, on the terminal date special
allocation for children's garments will be considered and por-
vided.

9. The imports into Austria will be permitted against the
import licence issued to the importer on the basis of the export
certificate issued at the time of endorsement by the Export
Promotion Council concerned or its upcountry representatives
on fulfilment of the terms and conditions stipulated for the pur-
pose from time to time. The export certificate is meant for the
buyer and hence the same, after obtaining from the Export Pro-
motion Council concerned, has to be forwarded by the shipper
to his buyer alongwith other related documents.

10. Whenever the consignment is ready for shipment, the
exporter shall submit the necessary shipping documents includ-
ing shipping bills in duplicate to the Export Promotion Council
concerned or its upcountry port representatives alongwith quota
certificate, if any, for obtaining quota endorsement. Alongwith
shipping documents, shippers shall submit a proforma applica-
tion in duplicate covering the details of goods under shipment for
issuing the necessary export certificate at the time of issuing
quota licensing endorsement. Thereafter, the documents
shall be submitted to the Customs for completion of the shipping
documents including shipping bills and other formalities. In the
case of readymade garments, the shipping documents including
shipping bills will also be submitted to the Apparel Export
Promotion Council, New Delhi or its upcountry port represent-
atives for quota endorsement before the shipping bills are noted
by the Customs at the port of shipment. In all these cases, the
shippers will be required to inform the Export Promotion Council
concerned or its upcountry port representatives from whom the
quota endorsement is obtained, the number and date of shipping
bills after the same are obtained from Customs.

11. In so far as handloom fabrics of the cottage industry,
handmade cottage industry products made of such handloom
fabrics woven garments made from such handloom fabrics and
traditional folklore handicraft textile products are concerned,
shipments will be permitted by the Customs for exports to
Austria on the basis of appropriate certificates issued by the
Textiles Committee or the All India Handicrafts Board, as the
case may be. For these items, no quota endorsement by the
Export Promotion Council concerned will be required for endor-
sement of the shipping bills by the Customs Authorities.

12. The Textile Commissioner, Bombay, or an officer designated by him will have a day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. A Co-ordination Committee with the Textile Commissioner as the Chairman and representatives of the Export Promotion Councils concerned will review the situation from time to time.

13. For garments and knitwear, performance bond for a value of 10% of the f.o.b. value of quota allotment will have to be submitted by the applicant alongwith the application for quota allotment on first-come, first-served firm contract basis. In the case of quota allocation on first-come, first-served ready goods basis, earnest money at the rate of Re. 1 per piece or 10% of the f.o.b. value, whichever is higher, will have to be deposited by the applicant at the time of quota endorsement. If the utilisation within the validity period of quota allotment/quota endorsement is not less than 90% full amount of earnest money deposit/performance bond will be refundable on production of evidence of export. If the utilisation of quota allocation is less than 90% penalty for the full amount of the performance bond will be imposed, and the full earnest money deposit will be liable to be forfeited. Further, if the surrender of quota is in excess of 25% of allotment, refusal of further quota allotment for such allottees may be considered. However, in conditions of force majeure, appropriate exemptions may be considered.

14. Exports will be allowed from any port in India.

15. The addresses of the Export Promotion Councils are as follows :-

(i) The Cotton Textiles Export Promotion Council, Engineering Centre 9, Mathew Road, 5th Floor, Bombay—400 004.

(ii) Apparels Export Promotion Council, Sahayog Building 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi—110019.

16. Persons to whom quotas are allotted in accordance with the above arrangements but who do not utilise them fully would be liable to disqualification from getting future quotas without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

17. The existing entry against S. No. 70(vii) on page 29, Section II of Export Policy 1978-79 shall be substituted as under :

1 2 3

“70(vii) Export of Mill made/ Export will be allowed under powerloom/handloom/ OGL. 3 subject to the following :

finished fabrics and misc. textile products of cotton (other than yarn, grey goods, terry towels and towelling) including ready-made garments and knitwear to Austria.

1. Against quota allotment by —
 - (a) The Cotton Textiles Export Promotion Council for fabrics and made-ups.
 - (b) The Apparels Export Promotion Council for garments and knitwears.

by endorsement on shipping bills.

2. Export of Handloom fabrics will be allowed without any quota restriction on the basis of certificate showing handloom origin from the Textiles Committee or All India Handicrafts board as the case may be.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.